

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2226 का उत्तर

छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्याएं

2226. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्या से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो आईआरसीटीसी ने वर्ष 2012 से रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाइसेंसधारियों द्वारा बेची जा रही चाय-पकौड़ा आदि वस्तुओं की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की है;
- (ग) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर छोटे खानपान लाइसेंसधारियों द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की दरें निर्धारित की गई थीं;
- (घ) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे, विशेष रूप से उत्तर रेलवे द्वारा चाय, कॉफी, पूरी, पकौड़ा आदि खाद्य वस्तुओं की दरों में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ङ) छोटे खानपान लाइसेंसधारियों की समस्याओं के समाधान तथा उनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) सरकार द्वारा एकसमान नीति तैयार करने तथा भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): रेलवे द्वारा समय-समय पर छोटे खान-पान लाइसेंसधारकों और उनके संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। उनकी चिंताओं की मैरिट के आधार पर जांच की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 53/2018 के तहत चाय/काँफी की दरों को संशोधित किया गया था और अन्य मानक मर्दों की दरों को वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 64/2019 के तहत संशोधित किया गया था। इसके अलावा, खानपान नीति 2017 में दी गई शक्तियों के तहत क्षेत्रीय रेलों और आईआरसीटीसी द्वारा अन्य ए-ला-कार्टे मर्दों की दरों में संशोधन किया जाता है।
